



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1946 (श0)  
(सं० पटना 520) पटना, मंगलवार, 18 जून 2024

सं० 08/आरोप-01-27/2021 सा0प्र0-6817  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
2 मई 2024

श्री विनोदानंद झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 524/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नालन्दा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रमादी मिलरों से बैंक गारन्टी/Deed of Pledge नियमानुसार प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5010 दिनांक 24.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-687 दिनांक 19.01.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत श्री झा से स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री झा का स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा (दिनांक 29.06.2022 एवं दिनांक 12.07.2022) प्राप्त हुआ, जिसमें विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि उठाये गये बिन्दुओं की गहन जाँच करायी जाय, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निदेश की चर्चा पर आरोप पत्र गठित किया गया है, उसकी राज्य खाद्य निगम द्वारा गलत व्याख्या की गयी है ताकि मिलरों को लाभ पहुँच सके एवं उनकी संपत्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में Auction करने से रोकी जा सके।

विभागीय पत्रांक-14309 दिनांक 17.08.2022 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-273 दिनांक 20.01.2023 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा पर राज्य खाद्य निगम का मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें निगम ने श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया। निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा के उपरान्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निगम के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी। निगम द्वारा मंतव्य दिया गया कि :-

- आरोपी पदाधिकारी द्वारा सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या को ध्यान से पढ़ा जाए तो आरोपी पदाधिकारी का कथन स्वयं गलत सिद्ध हो जाता है। ऐसे सिक्यूरिटीज जो inadequate हो अथवा encumbered हो श्री झा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और यह जवाबदेही जिला प्रबंधक की ही थी।

- (iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न कर सरकार की नीति एवं मंशा को गलत ठहराया जा रहा है। श्री झा को Pledged संपत्तियों की जाँच एवं सत्यापन करनी थी, परन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया एवं मनमाने ढंग से एकरारनामा कर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी। पूर्व में हुई लापरवाही के लिए श्री झा को मुक्त नहीं किया जा सकता है।
- (iv) भूमि से संबंधित सभी कागजात यथा खाता, खेसरा, रकवा एवं अन्य विवरणी का प्रावधान था, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया, फलतः निगम को आर्थिक क्षति हुई।
- (v) श्री झा द्वारा भंडारण क्षमता का उचित उपयोग एवं प्रबंधन किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है।
- (vi) श्री झा का यह कथन की उन पर बिहार पेंशन नियमावली का नियम-139 लागू नहीं होता है, सत्य नहीं है। आरोपी पदाधिकारी पर उक्त नियम लागू होता है।

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी एवं पाया गया कि प्रमादी मिलरों से कुल 87996448/-रु० की राशि वसूल की जानी थी, जिसमें से श्री झा द्वारा नीलामवाद दायर किये जाने के कारण कुल 21130456/-रुपये की राशि मिलरों द्वारा जमा की गयी थी एवं कुल 66865992/- रुपये की राशि वसूली हेतु शेष रह गयी थी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2542 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री झा के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के आलोक में उनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

श्री झा द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 24.03.2024) समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी। समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री झा द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उन्हीं बिन्दुओं/तथ्यों का समावेश किया गया है, जो पूर्व के स्पष्टीकरण में किया गया था।

अतएव श्री विनोदानंद झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 524/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नालन्दा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2542 दिनांक 12.02.2024 द्वारा अधिरोपित “दंड पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती 03 वर्षों तक करने” संबंधी दंड को यथावत बरकरार रखा जाता है।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+10-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>